



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

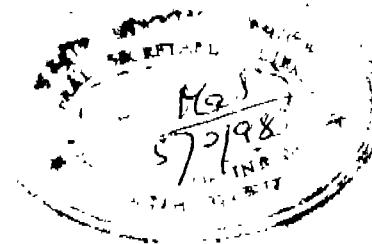
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii )

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 670 ]

No. 670]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1997/अग्रहायण 14, 1919

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1997/AGRAHAYANA 14, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुख्य, 5 दिसम्बर, 1997

प्रतिभूति संबिदा ( विनियम ) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन मगध स्टॉक एक्सचेंज के शासी मंडल को अतिष्ठित करते हुए आदेश

का. अ. 822 ( अ )—भाप्रविबो द्वारा किए गए मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन के निरीक्षण और निर्वाचित निदेशकों, लोक प्रतिनिधि निदेशकों, भाप्रविबो के नामनिर्देशित निदेशकों इत्यादि से प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के कार्य में अनियमिताएं और कुप्रबन्ध देखा गय था। संप्रेक्षित अनियमिताओं और कुप्रबन्ध के दृष्टांत निम्नलिखित हैं :—

- (i) प्रबन्ध परिषद् का प्रभावहीन कार्य और निर्वाचित सदस्यों में गुटबन्दी,
- (ii) आन्तरिक प्रशासन पद्धति का उप्प हो जाना,
- (iii) भाप्रविबो निदेशों का अननुपालन,
- (iv) भुगतान में विलम्ब,
- (v) सदस्यों के उच्च भुगतान और निपटान दायित्व, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के दायित्व हैं,
- (vi) सदस्यों का निम्न पूँजी आधार,
- (vii) निगरानी क्रियाकलापों का अनस्तित्व,
- (viii) बहुत अपरिनिर्धारित बुरी सुपुर्दगी दायित्व,
- (ix) माध्यस्थं मामलों के निपटारे में अनुचित विलम्ब,
- (x) भाप्रविबो निरीक्षण द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने में उपेक्षाशीलता।

मगध स्टॉक एक्सचेंज के प्रबन्ध परिषद् को प्रतिभूति संविदा (विनियम) 1956 की धारा 11 के अधीन 8 अक्टूबर, 1997 को एक नोटिस यह कारण बताने के लिए जारी किया था कि एक्सचेंज के प्रबन्ध परिषद् (इसमें इसके पश्चात् परिषद् के रूप में निर्दिष्ट) को कुप्रबन्ध और अनियमिताओं के उपर्युक्त दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए क्यों अतिष्ठित नहीं किया जाना चाहिए। परिषद् को नोटिस का लिखित में उत्तर देने और व्यक्तिगत सुनवाई की माँग करने, यदि ऐसा अपेक्षित है, के लिए 15 दिन दिए थे।

3. मगध स्टॉक एक्सचेंज के प्रबन्ध परिषद् ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने या उसमें लगाए गए किसी आरोपों से इंकार करने की परवाह नहीं भी। तारीख 28 अक्टूबर, 1997 के पत्र द्वारा 31 अक्टूबर, 1997 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया था। 31 अक्टूबर, 1997 को परिषद् के सदस्यों में से कोई भी उपस्थित नहीं था, और हालांकि ऐसा करना आवश्यक नहीं था, 21 नवम्बर, 1997 को व्यक्तिगत सुनवाई का एक अन्य अवसर दिया था। इस तारीख को भी, परिषद् के सदस्यों में से कोई भी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ था, सिवाय सुनी एस. कुरियन, भाप्रविबो की नामनिर्देशिती निदेशक के। वह प्रबन्ध परिषद् के विरुद्ध अनियमिताओं और कुप्रबन्ध के आरोपों से सहमत थीं।

4. भाप्रविबो को एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक से 20 अक्टूबर, 1997 के एक पत्र द्वारा परिषद् के सात सदस्यों द्वारा पारित परिपत्र संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई जो कथन करता है कि :

“संकल्प किया जाता है कि प्रबन्ध परिषद् ने अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 8-10-97 के पत्र सं. सीएस/4380/97 की विषयवस्तु नोट कर ली है और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्वोक्त पत्र के उपबंध-1 के अनुसार प्रबन्ध परिषद् के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर ध्यानपूर्वक विचार भी कर लिया है। आरोपों का सार मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन में आज की यथा विद्यमान सही और वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसीलिए, प्रबन्ध परिषद् भाप्रविबो से प्रतिभूति संविदा (विनियम) [प्रसं(वि)] अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन तुरन्त समुचित कारबाई करने का अनुरोध करता है ताकि विनिधानकर्ताओं का हित संरक्षित होता रहे।”

यह भी नोट किया गया है कि शेष छह निदेशकों में से, चार (निर्वाचित) निदेशकों ने संकल्प के विरुद्ध मत दिया है और एक सरकारी नामनिर्देशिती तथा एक निर्वाचित निदेशक ने संकल्प आपस नहीं किया था। पाँच निर्वाचित निदेशकों, जिन्होंने संकल्प के लिए मत नहीं दिया है, में से तीन के पूँजी पर्याप्तता बुरी सुपुर्दगी और निपटान के कारण दायित्व बकाया हैं।

5. सदर्य परिषद् को यह कारण बताने के लिए सम्यक् अवसर दिया गया है कि परिषद् क्यों अतिष्ठित नहीं की जानी चाहिए। परिषद् सदस्यों ने कारण बताने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित रहने की परवाह नहीं की। न ही परिषद् सदस्यों ने उनके विरुद्ध लगाए गए कुप्रबन्ध के दृष्टांतों पर कारबाई करना ठीक समझा। इसके विपरीत 13 परिषद् सदस्यों में से, 7 परिषद् सदस्यों ने कथन किया है कि भाप्रविबो द्वारा लगाए गए आरोप “मगध स्टॉक एक्सचेंज में यथा विद्यमान सही और वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं”।

6. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे विश्वास हो गया है कि मगध स्टॉक एक्सचेंज का परिषद् प्रसं(वि) अधिनियम के उपबंधों, एक्सचेंज की उप-विधियों और भाप्रविबो के निदेशों का उपयुक्त शासन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में असफल हुआ है। इसके परिणामस्वरूप दलाल सदस्यों और विनिधानकर्ताओं के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। भुगतान में विलम्ब, सदस्यों, जिनमें परिषद् सदस्य हैं, के भुगतान और निपटान दायित्व, वृहत् अपरिनिर्धारित बुरी सुपुर्दगी दायित्व, आन्तरिक प्रशासन का ठप्प हो जाना, भाप्रविबो निदेशों का अननुपालन ये सभी परिषद् के कुप्रबन्ध और कार्य न करने के दृष्टांत हैं। इसीलिए, यह आवश्यक है कि स्टॉक एक्सचेंज की सुरक्षा और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संव्यवहार विनियामक ढाँचे के अनुसार किए जाते हैं और विनिधानकर्ताओं के हित किसी भी प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं तुरन्त उपाय अपनाएं जाएँ।

7. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और तारीख 30 जुलाई, 1993 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 573 के साथ पढ़े जाने वाले प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और भाप्रविबो अधिनियम, 1992 की धारा 4(3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मगध स्टॉक एक्सचेंज परिषद् को एतद्वारा 8 दिसम्बर, 1997 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अतिष्ठित किया जाता है और श्री एस. एस. धनोआ, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) निवासी 40, मोनारीका एन्क्लेश, नई दिल्ली-110067 को एतद्वारा प्रबन्ध परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री एस. एस. धनोआ ऐसे व्यक्तियों की अतिरिक्त सहायता ले सकेंगे जो वह आवश्यक समझें।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2216/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 5th December, 1997

**Order U/s 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 Superseding the Council of Management of the Magadh Stock Exchange.**

**S.O. 822(E).**—Based on the inspection of the Magadh Stock Exchange Association conducted by SEBI and complaints from Elected Directors, Public Representative Directors, SEBI Nominee Directors etc. irregularities and mismanagement were observed in the functioning of the Stock Exchange. Following are the instances of irregularities and mismanagement observed :—

- (i) Ineffective functioning of the Council of Management and factionism among elected members,
- (ii) Break-down of Internal Administration system,
- (iii) Non-compliance of SEBI Directives,
- (iv) Delay in Pay Out,
- (v) High Pay Out and Closing Out Liability of Members, including liabilities of the Members of the Council of Management,
- (vi) Low Capital Base of the Members,
- (vii) Non-existence of Surveillance Activities,
- (viii) Huge Unsettled Bad Delivery Liability,
- (ix) Undue Delay in Disposal of Arbitration Cases,
- (x) Laxity in Rectifying Deficiencies pointed out by SEBI inspection.

2. The Council of Management of the Magadh Stock Exchange was issued a notice under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 on October 8, 1997 asking to show cause why the Council of Management (hereinafter referred to as Council) of the Exchange should not be superseded in view of the above instances of mismanagement and irregularities. The Council was given 15 days to reply in writing to the notice and seek personal hearing, if so required.

3. The Council of Management of the Magadh Stock Exchange did not care to reply to the show cause notice or deny any of the charges levelled therein. By a letter dated October 28, 1997 opportunity of personal hearing on October 31, 1997 was also given. None of the members of the Council appeared on October 31, 1997, and though not bound to do so another opportunity of personal hearing was given on November 21, 1997. Even on this date, none of the Council members, except i.e. Ms. S. Kurien, SEBI Nominee Director had appeared for personal hearing. She was in agreement with the charges of irregularities and mismanagement against the Council of Management.

4. SEBI by a letter dated October 20, 1997 received from the Executive Director of the Exchange a copy of the circular resolution passed by the seven members of the Council which states that :

“Resolved that the Council of Management has noted the contents of the letter No. CS/ 4380/97 dated 8-10-97 of Chairman, Securities and Exchange Board of India and has also carefully considered the charges levelled against the Council of Management as per Annexure-1 of the aforesaid letter of Chairman, Securities and Exchange Board of India. The substance of the charges reflects the true and factual position as existing in Magadh Stock Exchange Association today. Therefore, the Council of Management requests SEBI to take immediate appropriate action under section 11 of Securities Contracts (Regulation) [SCR] Act, 1956 so that the interest of the investors of the State is being protected.”

It is also noted that out of the remaining six directors, four (Elected) Directors have voted against the resolution and one Government Nominee and one Elected Director did not return the resolution. Out of the five Elected Directors, who have not voted for the resolution, three have outstanding liabilities on account of capital adequacy, pay out, bad delivery and closing out.

5. Due opportunity has been given to the Council of members to show cause why the Council should not be superseded. The council members have not cared to remain present at the personal hearing to show cause. Nor have the council members thought it fit to deal with the instances of mismanagement levelled against them. On the contrary out of 13 council members, 7 council members have stated that the charges levelled by SEBI "reflects the true and factual position as existing in Magadh Stock Exchange".

6. In view of the above facts, I am convinced that the Council of Magadh Stock Exchange has failed in ensuring proper governance and implementation of the provisions of the SC(R) Act, Bye-laws of the Exchange and SEBI directives. As a result of this the interest of the broker members and the investors are adversely affected. Delay in pay out, pay out and closing out liability of members including the members of the Council, huge unsettled bad delivery liability, break-down of internal administration, non-compliance of SEBI directives are all instances of mismanagement and non-functioning of the Council. Therefore, it is essential that immediate measures are adopted in order to ensure the safety and integrity of the stock exchange and to ensure that the transactions are carried out as per the regulatory framework and that the investors' interest are not adversely affected at any cost.

7. In view of above and in exercise of the powers conferred on me under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 to be read with Government of India Notification number S.O. 573 dated July 30, 1993 and Section 4 (3) of the SEBI Act 1992, the Council of the Magadh Stock Exchange is hereby superseded for a period of one year with effect from December 8th 1997 and Shri S. S. Dhanoa, IAS (Retd.) resident of 40, Monararika Enclave, New Delhi-110067 is hereby appointed as an Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management. Shri S. S. Dhanoa may take further assistance of such persons as he thinks it necessary.

[File No. SEBI/LE/2216/97]

D. R. MEHTA, Chairman